भारतीय एक्ट ईस्ट नीति और आसियान: इंडो-पेसेफिक क्षेत्रीय साझेदरी के निर्माण के विशेष सन्दर्भ में

Isha[1]; Dr Rachna Yadav[2]

[1]Research Scholar (Political Science), Dept. of Sociology and Political Science, Faculty of Social Sciences) Dayalbagh Educational Institute (Deemed University), Dayal Bagh Agra-282005
[2]Assistant Professor, Dept. of Sociology and Political Science, Faculty of Social Sciences) Dayalbagh Educational Institute (Deemed University), Dayal Bagh Agra-282005
Corresponding Author Email: singhisha151@gmail.com

सारांश- विगत वर्षो में यदि भारतीय सुरक्षा नीति की बात कि जाये तो पिछले कुछ दशकों से भारत की सुरक्षा चिंताओं में काफी बदलाव आया है| 1990 के दौरान "पूर्व की ओर देखों नीति" (एलईपी) के निर्माण के साथ ही एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में आसियान एक आवश्यक घटक के रूप में उभरा है| सन 2014 में भारत की एक्ट ईस्ट पालिसी में बदलाव के साथ और अधिक व्यापकता भी देखने को मिलती है| यदि वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक वातावरण में भी अमेरिका के पीछे हटने, चीन की आक्रमक स्थिति और बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिव के साथ ही साथ 'इंडो पेसेफिक' के भू-राजनीतिक निर्माण के साथ विशिष्ट बदलाव देखाई पड़ते है| क्षेत्रीय हितधारकों जैसे- आसियान, यूएसए, जापान, आस्ट्रेलिया और भारत अभी तक इंडो-पेसेफिक क्षेत्रीय निर्माण की अवधारणा के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना पर एक जैसा रुख नहीं अपना पायें है, यदि भारतीय एक्ट ईस्ट पालिसी की बात की जाये तो यह वर्तमान परिद्रश्य में एकदम सही सिध्द होती है क्योंकि भारत आसियान की केन्द्रीयता को बरकरार रखते हुये क्षेत्रीय सुरक्षा की एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है| भारतीय विदेश नीति, भारत-प्रशांत क्षेत्र में आपसी विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ तैयार करना चाहती है और नियम आधारित आदेश की खोज में एक विचारधारा वाले देशों जो पारदर्शिता, संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून, स्थिरता और मुक्त व्यापार ढांचे के लिए सम्मान को बढावा दें| इसी भू-राजनीतिक क्षेत्रीय निर्माण की एवं अंतर्राष्ट्रीय देशों के संग साझेदारी को ध्यान में रखते हुये यह शोधपत्र लिखा गया है जिसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय एक्ट ईस्ट पालिसी और भारत-प्रशांत क्षेत्रीय निर्माण की साझेदारी का वर्तमान परिदृश्य में अध्ययन करना है| प्रस्तुत शोधपत्र द्वितीय आंकड़ो पर आधारित है जिसकी शोधविधि वर्णात्मक एवं विवरणात्मक है|

प्रमुख शब्द- एक्ट ईस्ट पालिसी, आसियान, इंडो-पेसेफिक भू-राजनीति, भारत-आसियान सम्बंध |

I. परिचय

भारत और पूर्वी एशिया के मध्य राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक और सामाजिक-सांस्क्रतिक रहे है| पूर्वी एशिया में भारत के साथ धार्मिक क्षेत्र में हिन्दू धर्म और बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार को किय जाता रहा है| इसका उल्लेख पुरातात्विक अवशेष व शिलालेखों में होता है| दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों के साथ भारत के व्यापारिक, सांस्क्रतिक और समुद्री संबंधो में औपनिवेशिक शक्तियों के कारण बाधाये आई किन्तु 1992 में भारत की पूर्व की ओर देखो नीति ने इन बाधाओ को दूर किया 1992 के पूर्व को ओर देखो से पहले भी दिल्ली में आयोजित 1947 का एशियाई सम्बंध सम्मेलन और 1955 बाइंग सम्मेलन आसियान देशों से संबंध मजबूत करने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण प्रयास थे| शीत युद्ध के दौरान क्षेत्रीय भू-राजनीति के कारण सम्बंध तनावपूर्ण हो गये| भारत ने हमेशा से ही कई अलग-अलग तरीको से पूर्व के साथ जुड़ा हुआ है| पूर्व की ओर देखो (एलईपी) भारत के पूर्व के जुडाव को चार चरणों में वर्गीक्रत करता है- पूर्व-ओपनिवेशिक काल में, ब्रिटिश साम्राज्यवाद में, स्वतंत्रता के दौरान और 1991 के बाद से| पूर्व से भारत के सबसे पहले के सम्बंध धार्मिक व व्यापारिक रहे, स्वतंत्रता के बाद भारत की नये स्वतंत्र एशियाई व अफ्रीकी देशों को एकिकृत करना| पंचशील ने उभरते हुये एशियाई देशों के बीच एक क्षेत्रीय व्यवस्था प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम था| यह नेहरु का सिद्धांत साकार नहीं हो पाया और 1980 के दशक में भारत नये उभरते एशियाई देशों से अलग हो गया| शीत युद्ध के कारण क्षेत्रीय भू-राजनीति के कारण भारत दक्षिण एशियाई देशों से अलग हो गया|

भारत ने अपने संबंधो को बनाये रखने के लिए गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया, यूएसएसआर के प्रति झुकाव के साथ अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आसियान देशों के खिलाफ एक नया दृष्टिकोण अपनाया अथार्त एक प्रकार से क्षेत्रीय भू-राजनीति और शीत युद्ध ने भारत व आसियान के संबंधो को निर्धारण किया और भारत-चीन युद्ध के कारण विभाजन भी कर दिया| भारत के लिए आसियान के साथ धनिष्ट संबंध रखने के कारण आसियान देशों के द्विपक्षीय संबंध रहा है|

II. शोधविधि

प्रस्तुत शोधपत्र में वर्णात्मक एवं विवरणात्मक शोध पद्वति का प्रयोग किया गया हैप्रस्तुत शोधपत्र द्वितीयक स्त्रोतों पर आधारित है|

III. अध्ययन के उद्देश्य

1- भारत के आसियान देशों के साथ संबंधो का अध्ययन करना|

2- भारत के प्रशांत क्षेत्र की भू-राजनीति का अध्ययन करना|

IV. भारत-आसियान संबंध

लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट तक भारत का पूर्व की ओर देखो नीति कई कारणों से प्रभावित हुई थी| शीत युद्ध के बाद भारत का रुख आसियान देशों के प्रति अधिक बड गया| चीन के आर्थिक दवाब और आसियान देशों के सहयोग से भारत ने आर्थिक प्रगति को विकसित करना प्रारंभ कर दिया है| 1996 में विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में अधिकारिक तौर पर दिखाई दिया की भारत ने आसियान देशों से अपना जुड़ाव मजबूत कर दिया| एलईपी ने दक्षिण पूर्व को एशिया के साथ अपने आर्थिक संबंधो के पुर्ननिर्माण के उद्देश्य से लागू की गई| आसियान देशों के द्वारा भारत के नवीन कदम के साथ, व्यापार और आर्थिक संबंधो से जापान व पश्चिमी देशों और चीन पर अपनी निर्भरता को कम कर सकने की पहल की गई है|

1995 में आसियान शिखर सम्मेलन में बैकांक में पार्टनर बन गया| बाद में 2002 में सम्मेलन में स्तर का भागीदार बन गया| इसके आलावा भारत 1996 में आसियान क्षेत्रीय मंच का सदस्य बना इस प्रकार सभी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधो सुरक्षा और सामरिक सहयोग में भारत की बढती भागीदारी दिखाई दी| 2003 में भारत दक्षिण पूर्व एशिया में मित्रता और सहयोग की संधि में शामिल हुआ जो भारत को दक्षिण पूर्व एशिया में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और विकास के साझा हितों का संकेत देता है| भारत ने (2019) में आसियान के साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने में सहयोग पर हस्ताक्षर किये| 2009 में भारत में मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किये और 2012 में भारत और आसियान ने रणनीतिक साझेदारी की| 2014 में भारत-आसियान ने व्यापार सेवा और निवेश समझौता किया जो 2015 को प्रभावी हुआ|

2014 में भारत ने नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एलईपी से एईपी (एक्ट ईस्ट पालिसी) में बदल दिया| भारत आसियान संबंधो में एलईपी से एईपी में बदलाव किया| इसका एक कारण यह था की हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा बढा है| 2017 में शिखर वैठक हुई, 2018 में गणतंत्र दिवस पर सभी आसियान सदस्य देशों को आमन्त्रित किया| यह कनेक्टिविटी व्यापार, सूचना विनियम एईपी को बढावा देता है|

V. भारत-आसियान और भारत-प्रशांत की क्षेत्रीय समस्याये

एईपी एक क्षेत्रीय ठांचे के रूप में भारत-प्रशांत और आसियान के बीच एक सेतु का कार्य करता है| भारत अन्य क्षेत्रीयशक्तियों के साथ मिलकर भी रहना चाहता है जिससे उसके हितों और क्षितिज के प्रभाव को विस्तृत कर सकें| इसके आलावा एशिया-प्रशांत का क्षेत्रीय ढांचा इंडो-पेसिफिक के साथ एक बड़े भू-राजनीतिक निर्माण में परिवर्तित हो रहा है जिसने इस क्षेत्र के समक्ष चुनौती दी है| जापान और चीन के बढते हुये रुख ने प्रशांत महासागर क्षेत्र को चिंतित बिषय बना दिया है| हिन्द प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और आर्थिक हित भारत के लिये चिंता का बिषय बन गई है| चीन की आधिपत्य नीति व आसियान देशों से जटिल संबंध इसे अधिक जटिल बना देते है| चीन पहले से अपना अधिपत्य बनाने में लगा है| भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत का सुरक्षा के परिपेक्ष्य में अधिक महत्वपूर्ण उपस्थिति के साथ-साथ क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए एक रुपरेखा देने की आकांक्षा देना प्रारम्भ कर दिया| भारत-प्रशांत क्षेत्र की क्षेत्रीयता भू-राजनीति का केंद्र बन गया है|

VI. हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में भारत के सुरक्षा और आर्थिक हित

हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में भारत के आर्थिक और सुरक्षा के हितों का घनिष्ठ संगम बन गया है| भारत-प्रशांत की आर्थिक ताकत और उभरता हुआ सुरक्षा एक प्रासंगिक विषय बन हुआ है| चीन के आर्थिक, राजनीति और सुरक्षा के दबदबे का एक निर्विवाद प्रभुत्व है| इस क्षेत्र में चीन की गतिविधियो को देखते हुये क्वाड भारत के सुरक्षा हित के लिए बाध्यकारी प्रतीत होता है| भारत के लिए यह एक नया प्रश्न यह भी है कि भारत आसियान देशों व क्वाड के मध्य कैसे संतुलन लायेगा, यदि भारत क्वाड में सक्रिय रूप से शामिल होगा तो एईपी के उद्देश्यों को भी पूरा करना पड़ेगा| हालांकि क्वाड आसियान केन्द्रित क्षेत्रीयता का पूरक है क्योंकि यह आसियान केन्द्रियता को स्वीकार करता है|

VI. निष्कर्ष

भारत एक शक्तिशाली देश है, जिसकी विदेश नीति भाईचारे (आदर्शवादी) की रही है| भारत अपने राष्ट्र हितों को ध्यान में रखकर अपनी नीतियाँ बनाता है| भारत आसियान देशों के साथ मैत्रीपूर्ण, आर्थिक हित और व्यापारिक संबंधो को निभाता है| किन्तु चीन के बढती कूटनीति के कारण भारत की चिंताए हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के लिए बढ गई है जिसको सुरक्षित करने के लिए भारत को एक नई रणनीति तैयार करनी पड़ेगी और साथ ही अपने संबंधो को आसियान देशों के साथ अधिक मजबूत बनाये रखना होगा|

सन्दर्भ

1. Arshad, (2017). Act east policy south east asia and indo-pacific maritime security cooperation. International Journal of Creative research thought, ISSN:2320-2882

2. Bajpaee, C. (2017). Dephasing India's Look East/Act eat policy. International Journal of Creative research thought, ISSN:1793-284X
3. Ngaikching, & Pande, A., (2020). India's act east policy and asean building a regional order through paertnership in the indo-pacific. International Studies, DOI:10.1177/002088179885526
4. Lal, B. (2021). Evalution of look east to act east policy. Contempory Issues in IR